कोर्ट ने केन्द्र से कहा, किस तरह का प्रदूषण नियंत्रण कर रहे हैं

नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर (ए)। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र से सवाल किया कि ऐसा क्यों है कि दिल्ली के ज्यादातर प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) केन्द्र या तो काम नहीं कर रहे हैं या बंद होने वाले हैं। न्यायालय ने केन्द्र से पूछा, ''आप किस तरह का प्रदूषण नियंत्रण कर रहे हैं'' न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने सरकार द्वारा सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट पर गौर करने के बाद केन्द्र से यह सवाल पूछा। केन्द्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) ए एन एस नादकर्णी ने अदालत से कहा कि विस्तृत कार्य योजना पर बैठकें हुई हैं। इस कार्ययोजना का उद्देश्य दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटना है। पीठ ने एएसजी से पूछा, ''इन सब का क्या उपयोग है दिल्ली में कितने प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र हैं एएसजी ने कहा कि यहां करीब 200 पीयूसी केन्द्र हैं। इस पर पीठ ने सवाल किया, ''200 में से करीब 170 पीयूसी केन्द्र काम नहीं कर रहे हैं। आप किस तरह का प्रदूषण नियंत्रण कर रहे हैं'' पीठ ने कहा कि इस विषय पर जनवरी में आगे की सुनवाई की जाएगी।

माल्या की बढ़ी मुश्किलें, पटियाला हाउस कोर्ट ने संपत्ति अटैच करने के दिए आदेश

नई दिल्ली , 11 अक्टूबर (ए)। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की मुश्किले बढ़ गई हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने माल्या की बेंगलुरु की संपत्ति अटैच करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने वीरवार को फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन एक्ट (फेरा) के उल्लंघन के मामले में सुनवाई की जिस दौरान यह फैसला सुनाया गया। दरअसल ईडी के समन के बाद उपस्थित नहीं होने पर माल्या को भगोड़ा घोषित करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। पहले की गई सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि माल्या की उपस्थिति के लिए उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। माल्या के दफ्तर और आवास पर नोटिस भेजा यहां तक कि अखबारों में भी विज्ञापन दिया था। ईडी का आरोप है कि विजय माल्या ने 1996, 1997 और 1998 में लंदन और यूरोपीय देशों में आयोजित फॉर्मूला वन चैंपियनशिप में किंगफिशर का लोगो दिखाने के लिए एक ब्रिटिश फर्म को दो लाख अमेरिकी डॉलर दिए थे। ईडी के मुताबिक माल्या ने ये रकम रिजर्व बैंक की बिना पूर्व अनुमति के दिए थे जो फेरा के नियमों के उल्लंघन के तहत आता है।

रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच अब सरकार किस्तों पर देगी इंडक्शन चूल्हा

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (ए)। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार लोगों को कम कीमत पर खाना पकाने के लिए एक और विकल्प उपलब्ध कराएगी। उज्ज्वला योजना की तर्ज पर आसान किस्तों में इंडक्शन चूल्हा बांटा जाएगा। इससे हर परिवार को सालाना पंद्रह सौ रुपए की बचत होगी। इंडक्शन चूल्हा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को उपलब्ध कराए जाएंगे। एक मुश्त कीमत देकर भी इंडक्शन चूल्हा खरीदा जा सकता है। किस्तों पर चूल्हा खरीदने वाले परिवारों को हर माह बिजली के बिल के साथ किस्त अदा करनी पड़ेगी। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने इंडक्शन चूल्हे का प्रस्ताव बिजली मंत्रालय को भेज दिया है। सिंगल इंडक्शन चूल्हे की कीमत करीब 800 रुपए और डबल इंडक्शन चूल्हे की कीमत लगभग 1500 रुपए होगी। सामान्य परिवार में इंडक्शन के जरिए खाना पकाने में करीब सौ यूनिट प्रति माह खर्च होगी। रसोई गैस सिलेंडर औसतन 22-25 दिन चलता है। इस वक्त एलपीजी गैस की कीमत राजधानी दिल्ली में 879 रुपए प्रति सिलेंडर है। सरकार ने इस साल दिसंबर तक सौभाग्य योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 2022 तक सभी को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने की रुपरेखा भी तैयार कर ली गई है। इसलिए, इंडक्शन चूल्हे के लिए बिजली की उपलब्धता कोई समस्या नहीं है।

अज्ञात लोगों की गोलाबारी में एसपीओ घायल

श्रीनगर, 11 अक्टूबर (ए)। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में अज्ञात बंदूकधारियों ने कल रात एक विशेष पुलिस अधिकारी को निशाना बनाते हुए गोलीबारी कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एसपीओ बिलाल अहमद गनी पर कल रात पुलवामा के करीमाबाद में अज्ञात लोगों ने बहुत ही नजदीकी से गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में घायल गनी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और बंदूकधारियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने खोजी अभियान छेड़ दिया है। गौरतलब है कि कश्मीर में आतंकियों ने पुलिसकर्मियों को अपने निशाने पर ले रखा है। दहशतगर्द डर और खौफ का माहौल बनाकर पुलिसकर्मियों को नौकरियां छोडने को कह रहे हैं। इससे पहले भी वे कई एसपीओ और कांस्टेबल स्तर के कर्मियों को अगवा कर चुके हैं।

मधेसी पार्टी ने ओली सरकार से समर्थन वापस लेने की दी चेतावनी

काठमांडू, 11 अक्टूबर (ए)। नेपाल में संविधान में संशोधन की मांग न माने जाने पर मुख्य मधेसी पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी-नेपाल (आरजेपी एन) ने प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली नीत सरकार से समर्थन वापस लेने की चेतावनी दी है। सोमवार को प्रधानमंत्री ओली को ज्ञापन सौंपने वाले आरजेपी एन नेताओं ने चेताया है कि अगर सरकार उनकी मांगें मानने में विफल रहती है तो पार्टी दिवाली के बाद उनकी सरकार को दिया अपना समर्थन वापस ले लेगी। आरजेपी एन ने मधेसी, थारु, मुस्लिमों एवं जनजातियों की मांगों पर ध्यान देने के लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। आरजेपी-एन के अध्यक्ष मंडल के सदस्य राजेंद्र महतो ने कहा कि यह उनकी आखिरी चेतावनी है और अगर सरकार इसे अनसुना करती है तो त्योहारों के बाद सरकार से समर्थन वापस लेकर नया आंदोलन शुरू करेंगे। पूर्व वाणिज्य मंत्री महतो ने कहा कि सरकार मांगों को नहीं सुन रही है और संविधान में संशोधनों को भी नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। 2015 में नेपाल को 7 प्रांतीय इकाइयों में विभाजित करने वाले अपनाए गए नए संविधान में मधेसियों को अधिकारहीन करने की खबरों के बाद ओली के पहले कार्यकाल के दौरान छह महीने लंबा आंदोलन चला था जिसमें 50 लोग मारे गए थे। मधेस में ज्यादातर भारतीय मूल के लोग हैं और तराई के निवासी हैं। मधेसी पार्टी दक्षिणी तराई क्षेत्र के वासियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है।

पराली से होने वाले प्रदूषण से मिलेगी निजात, वैज्ञानिकों ने ढूंढी नई तरकीब

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (ए)। मौसम के करवट बदलते ही राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली की खराब हवा का एक कारण किसानों द्वारा जलाई जा रही पराली भी है। दरअसल फसल काटने के बाद खेत में बची पराली को किसान जला देते हैं जिसके कारण हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। पिछले तीन साल से राजधानी दिल्ली की हवा काफी खराब हुई है। पिछले साल तो दिल्लीवासियों को सांस तक लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों और वातावरण के लिए समस्या का कारण बनी पराली को अब वैज्ञानिक एक अलग ढंग से प्रयोग में लाएंगे। भारतीय वैज्ञानिकों ने इससे हाइब्रिड कंपोजिट तैयार करने की तकनीक ढूंढ़ ली है जिसका इस्तेमाल घरों की छतें, दीवारें, फर्श आदि बनाने के लिए किया जा सकता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) की प्रयोगशाला 'एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट'(एम्प्री) के वैज्ञानिक डॉ. अशोकन पप्पू ने पराली समेत अनेक प्रकार के कूड़े को हाइब्रिड कंपोजिट में बदलने की तकनीक विकसित की है। उन्होंने बताया कि पराली से बनी शीट सागवान की लकड़ी की तुलना में चार गुणा मजबूत, उससे हल्की और 30 प्रतिशत सस्ती है। यह आग से पूरी तरह सुरक्षित है। यह मौसम, नमी और फंगस से सुरक्षित है। उन्होंने सीमेंट उद्योग से निकलने वाले' फ्लाई ऐस' में फाइबर मिलाकर एक दूसरा हाइब्रिड कंपोजिट तैयार किया है जो सागवान की लकड़ी से 10 गुणा मजबूत और 40 प्रतिशत सस्ता है। संगमरमर उद्योग से निकलने वाले छोटे-छोटे टुकड़ों के हाइब्रिड कंपोजिट से पेपरवेट तैयार किए गए हैं जिनकी कीमत मजह 25 से 30 रुपए है। खास बात यह है कि यह पेपरवेट गिरने के बावजूद टूटता नहीं। डॉ. पप्पू ने बताया कि वह 15 वर्ष से इस तकनीक पर काम कर रहे थे तथा उत्पाद और उत्पादन प्रक्रिया दोनों का भारत तथा अमेरिका में पेटेंट कराया जा चुका है। करीब डेढ़ साल पहले छत्तीसगढ़ की कंपनी इको ब्राइट शीट को यह तकनीक हस्तांतरित की गई थी। इन उत्पादों की मांग इतनी है कि कंपनी अपनी पूरी क्षमता पर उत्पादन करते हुए भी मांग पूरी नहीं कर पा रही है। उसने महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में अपने संयंत्र लगाए हैं जबकि एक संयंत्र पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने लगाया है। इन पदार्थों से इस्तेमाल छह फीट गुणा आठ फीट आकार तक के शीट, फर्श और दीवारों के टाइल्स, छत की शीट, दरवाजे तथा पार्टिशन पैनल तैयार करने में किए जा सकते हैं। इनके उत्पादन की प्रक्रिया काफी सरल है तथा इसमें ऊर्जा की खपत भी कम होती है। ये पूरी तरह किफायती हैं और इनमें रखरखाव का झंझट नहीं होता।

दिल्ली के अफसरों पर हमारा कंट्रोलः केंद्र

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (ए)। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दलील दी कि दिल्ली सरकार में तैनात अधिकारी उसके नियंत्रण और निगरानी में हैं। केंद्र का कहना था कि इस शक्ति का इस्तेमाल राष्ट्रपति की ओर से दी गई शक्तियों के तहत उप राज्यपाल करते हैं। दिल्ली में तैनात ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर और कंट्रोल को लेकर अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने इससे पहले कहा था कि दिल्ली एक राज्य नहीं, बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो खुद में एक वर्ग है। कोर्ट का यह भी कहना था कि उप राज्यपाल को दिल्ली की मंत्री परिषद की सहायता और सुझाव के साथ कार्य करना होगा।

अब एक नियमित बेंच दिल्ली में निर्वाचित सरकार और केंद्र के बीच सत्ता के संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। अभी दो सदस्यीय बेंच 2015 के केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन की वैधता की समीक्षा कर रही है। इस नोटिफिकेशन में दिल्ली में तैनात अधिकारियों पर नियंत्रण की शक्ति होने का दावा किया गया था।

सीनियर एडवोकेट आर्यमन सुंदरम ने यह भी दावा किया कि अधिकारियों का केवल उप राज्यपाल ट्रांसफर कर सकते हैं। वह जस्टिस ए के सीकरी और अशोक भूषण की बेंच के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। बेंच ने उनसे पूछा था कि अगर सरकार का ब्यूरोक्रेट्स पर नियंत्रण नहीं होगा तो वह कैसे कार्य करेगी। जस्टिस सीकरी ने कहा, उनके तैनात होने पर उनके साथ वे कैसे कार्य करेंगे

जस्टिस भूषण का कहना था, सरकार कैसे कार्य करेगी सुंदरम ने इसके जवाब में कहा, प्रशासन में अभी तक कोई समस्या नहीं थी। इससे पहले भी केंद्र और दिल्ली में अलग राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार पर सहयोग नहीं करने और अधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति मांगने का आरोप लगाया।

उनका कहना था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भी दिल्ली सरकार के समान स्थिति में है और वह इन अधिकारियों के ट्रांसफर जैसे मुद्दों से निपटेगा। सुंदरम ने कहा, एक स्रोत के बिना शक्ति नहीं हो सकती। शक्ति का कोई स्रोत नहीं है। सुंदरम ने कहा कि कोई अन्य व्याख्या संविधान के खिलाफ होगी। उनका कहना था कि यह शक्ति राष्ट्रपति की ओर से उप राज्यपाल को दी गई है। किसी सहायता या सलाह की आवश्यकता नहीं है।

अनिल अंबानी की चौकीदारी कर रहे हैं मोदी : राहुल गांधी

नई दिल्ली , 11 अक्टूबर (ए)। राफेल डील को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच चल रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी हैं और वह रक्षा सौदे में हुए भ्रष्टाचार में सीधे तौर पर लिप्त हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राफेल खरीद में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। संसद की संयुक्त समिति से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राफेल खरीद में जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एचएएल से ठेका छीनकर कर उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी को यह काम दिया गया है, उससे साफ है कि खुद को देश का चौकीदार बताने वाले मोदी अब अनिल अंबानी की चौकीदारी कर रहे हैं। यह सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और मोदी ने यह भ्रष्टाचार किया है। इसलिए उन्हें इस बारे में जवाब देना चाहिए या फिर वह इस्तीफा दें। राहुल ने कहा कि 30 हजार करोड़ प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी की जेब में डाले। मोदी सरकार में हालात ये हैं कि अमीर व्यक्ति बैंक में जाता है तो बैंक के दरवाजे जादू से खुल जाते हैं।

गुजरात में हिंसा पर इशारों में बोले मोदी, बांटने से बढ़ती हैं खुशियां, कांग्रेस पर लगाया बांटने का आरोप

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (ए)। गुजरात में दूसरे राज्यों के मजदूरों के साथ हिंसा के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी ने इशारों में अपनी बात रखी है। बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खुशिया साझा करने से बढ़ती हैं। पीएम मोदी ने इस टिप्पणी के जरिए प्रवासी मजदूरों को लेकर जारी हिंसा से जूझ रहे गुजरात के लिए अहम संदेश दिया। इस टिप्पणी के जरिए पीएम मोदी ने गुजरात के लोगों को दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर बांटों और राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया।

नमो ऐप के जरिए 5 लोकसभा सीटों रायपुर, मैसूर, दमोह, करौली-धौलपुर, आगरा के बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने यह बात कही। पीएम मोदी ने कहा, समाज में कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस लंबे समय से बांटो और राज करो की नीति पर चलती रही है। उन्होंने सिर्फ एक परिवार के हितों के लिए समाज को बांटने का काम किया, लेकिन बीजेपी सभी के कल्याण और समाज की एकता में विश्वास करती है। बता दें कि गुजरात में बिहार और यूपी के मजदूरों के खिलाफ हिंसा के चलते हजारों लोग अपने राज्यों की ओर पलायन कर चुके हैं। बीजेपी ने कांग्रेस लीडर अल्पेश ठाकोर पर इस हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने कहा, हम समाज में नफरत नहीं फैलाते और बांटने का काम नहीं करते। हमारा मंत्र सबका साथ-सबका विकास है। लेकिन वे (कांग्रेस) समाज को बांटकर और नफरत फैलाकर खुद को मजबूत करना चाहते हैं। दमोह के एक बीजेपी वर्कर के सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने यह बात कही।

दोनों तरफ से खेल रहे हैं पुतिन, सोनिया गांधी के केजीबी से रिश्ते का रिकॉर्ड दें: सुब्रमण्यन स्वामी

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (ए)। विवादित बयान देकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने इस बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद स्वामी ने कहा है कि सुभाषचंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री की फाइल को सार्वजनिक कर पुतिन को साबित करना चाहिए कि वह हमारे दोस्त हैं। स्वामी यहीं नहीं रुके, बल्कि सोनिया गांधी और केजीबी के कनेक्शन का आरोप लगाते हुए पुतिन से इसके दस्तावेज भी मांग लिए।

आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन पिछले दिनों भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरे के दौरान रूस और भारत के बीच बहुप्रतिक्षित S-400 हवाई रक्षा प्रणाली का सौदा हुआ। अमेरिकी आपत्तियों और प्रतिबंध के खतरे के बावजूद भारत ने यह अहम रक्षा करार किया है। इस बीच सुब्रमण्यन स्वामी का यह बयान सामने आया है। सांसद स्वामी ने पुतिन के बहाने यूपीए चेयरपर्सन और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा है। स्वामी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुतिन को बताना चाहिए कि सोनिया गांधी हाल में दो बार रूस उनसे मिलने क्यों गई। स्वामी ने सोनिया गांधी पर रूस की जासूसी एजेंसी केजीबी से भी कनेक्शन का आरोप लगाते हुए कहा कि पुतिन को सोनिया व उनके पिता के केजीबी से संबंधों के डॉक्युमेंट हमें सौंपने चाहिए। आपको बता दें कि सुब्रमण्यन स्वामी गांधी परिवार के सर्वाधिक मुखर आलोचकों में से एक रहे हैं। स्वामी ने नैशनल हेरल्ड केस में भी गांधी परिवार के खिलाफ याचिका लगा रही है। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने स्वामी पर आरोप लगाया था कि वह सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देकर नैशनल हेकल्ड केस की सुनवाई को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वोरा की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील आर.एस.चीमा ने कहा था कि स्वामी ट्वीट कर आरोपियों का चरित्र हनन कर रहे हैं।

राजधानी में बंद होंगी 27 हजार फैक्ट्रियां और अवैध कॉलोनियां

नईदिल्ली ,11 अक्टूबर (ए)। उच्चतम न्यायालय ने राजधानी में सीलिंग पर किसी तरह की राहत का संकेत दिये बिना गुरुवार को कहा कि गैर-कानूनी और अवैध निर्माण की सीलिंग के लिए अग्रिम नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से उस नियम को खत्म किए जाने पर जवाब मांगा है, जिसके हिसाब से सीलिंग करने के 48 घंटे पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 27 हजार से ज्यादा अवैध और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बंद करने का भी निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि पिछले सात सितंबर को शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेष कार्य बल (एसटीएफ) को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि लगता है कि इन पर दबाव है, खासकर व्यापारियों का। न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा था कि दिल्ली से मुंबई नहीं, बल्कि कन्याकुमारी तक की दूरी का यहां अवैध कब्जा है। न्यायमूर्ति लोकुर ने सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जहां भी रिहायशी क्षेत्रों में अवैध तरीके से औद्योगिक इकाइयां चलायी जा रही हैं, उन्हें 15 दिनों के भीतर सील किया जाये। कोर्ट ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मॉनिटरिंग कमिटी के गठन को 15 साल हो चुके हैं लेकिन कई इंडस्ट्रियल यूनिट अभी तक दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में चल रही हैं।

अब तक की सबसे लंबी दूरी तय करेगा नासा का अंतरिक्ष यान

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की दहलीज पर पहुंच गई है। उसका एक अंतरिक्ष यान अब तक की सबसे लंबी दूरी तय कर दूरस्थ पिंड तक पहुंचने वाला है। संभावना जताई जा रही है कि नए साल पर यह रिकॉर्ड बन जाएगा। दरअसल, नासा का न्यू होराइजन प्रोब अंतरिक्ष यान सबसे दूर कुइपर बेल्ट में स्थित अल्टिमा थुले नामक पिंड तक पहुंचने वाला है, जो कि किसी अंतरिक्ष यान के सबसे दूर स्थित किसी पिंड तक पहुंचने का रिकॉर्ड होगा।

नासा के बयान के मुताबिक, इस अंतरिक्ष यान ने तीन अक्टूबर को उस पिंड की स्थिति का पता लगाने में सफलता हासिल की। इसके लिए अंतरिक्ष यान को साढ़े तीन मिनट का समय लगा। हालांकि, इसके लिए अंतरिक्ष यान को इतनी देर के लिए अपनी कक्षा से थोड़ा हटना पड़ा और इस दौरान उसकी गति 2.1 मीटर प्रति सेकंड रह गई। बयान में कहा गया है कि एक जनवरी, 2019 को इसके अल्टिमा

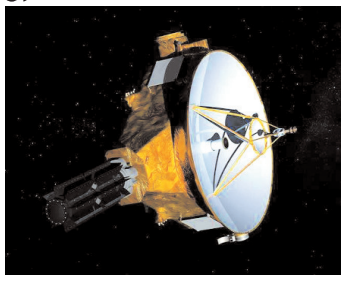

थुले नामक पिंड तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्ष 2014 में इस पिंड का आधिकारिक नाम एमयू69 रखा गया था। अमेरिका के साउथवेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख्य जांचकर्ता एलन स्टर्न कहते हैं, इस अभियान के जरिये हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। हम विश्व इतिहास में सबसे अधिक दूरी तय करने के करीब पहुंच गए हैं। पिंड जहां स्थित है वह दूरी प्लूटो से भी एक अरब मील अधिक है। अल्टिमा थुले धरती से 6.6 अरब किलोमीटर दूर है। यह सर्वाधिक दूर मौजूद पिंड है, जिस तरफ कोई अंतरिक्ष यान बढ़ रहा है।

नासा के मुताबिक, पिछले सप्ताह जब न्यू होराइजन की स्थिति को सुधारा गया तब वह धरती से 6.35 अरब किलोमीटर दूर था। यह पहली बार है जब इतनी दूरी पर किसी अंतरिक्ष यान की स्थिति में सुधार किया गया है।